

दि कर्मिक पोस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 10, अंक : 18

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 18 दिसंबर 2024 से 24 दिसंबर 2024

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिए सरकारी सहयोग जरूरी-रिपोर्ट

मुंबई। साल 2030 तक भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत सरकार को ऑफशोर विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) और ग्रीन हाइड्रोजन (जीएच₂) जैसे क्षेत्रों में मदद बढ़ानी होगी। यह बात एक नई रिपोर्ट में सामने आई है।

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नॉलॉजी एंड पॉलिसी (सीएसटीईपी) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईआईएसडी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सोलर पीवी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज (बीईएसएस) के लक्ष्यों को बिना अतिरिक्त सरकारी वित्तीय मदद के पूरा कर सकता है, लेकिन ऑफशोर विंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सरकारी निवेश बढ़ाने की जरूरत है।

आईआईएसडी की पॉलिसी एडवाइज़र और रिपोर्ट की सह-लेखिका स्वाति रायजादा ने कहा, भारत की स्वच्छ ऊर्जा की महत्वाकांक्षा प्रेरणादायक है, लेकिन इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए साहसिक नीतियों और निवेश की आवश्यकता है। खासकर ऑफशोर विंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सतत सरकारी सहयोग जरूरी है। भारत की 71 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए लगभग 9,000 करोड़



रुप प्रति गीगावाट का अतिरिक्त सरकारी सहयोग चाहिए। यह मदद न केवल इस क्षेत्र को परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बराबर लाएगी, बल्कि इसे भविष्य में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने में भी सक्षम बनाएगी। साल 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 2.8 लाख करोड़ रुपए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 19,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सरकारी मदद की आवश्यकता है। यह निवेश न केवल ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी लाएगा। रिपोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि छोटे लेकिन त्वरित सरकारी निवेश से प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही दीर्घकालिक आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी सुनिश्चित होंगे। स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। रायजादा ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र में समय पर किया गया निवेश भारत की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत करेगा।

बाढ़ से निपटने में अहम भूमिका निभा सकती है खेती की जमीन, वैज्ञानिकों ने बताई वजह

मुंबई। नदियों के संगम के आसपास संरक्षित खेती की जमीन बाढ़ को कम करने में मदद कर सकती है। टोक्यो स्थित मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की अगुवाई में किए गए एक शोध में यह दावा किया गया है।

इस शोध में कहा गया है कि सांख्यिकीय विश्लेषण के बाद पता चला कि जिन इलाकों में पानी को जमा करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, वहां खेती करने पर बाढ़ की संभावना कम हो जाती है। यह शोध जहां किया गया, वह कृषि भूमि नदी के एक संगम के पास स्थित थी। शोधकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि उनके शोध के निष्कर्ष से यह पता चलेगा कि भूमि का उपयोग करने का प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? यहां यह उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जिस तरह बेमौसमी घटनाएं बढ़ी हैं, उससे बाढ़ का खतरा एक बड़ा चिंता का कारण बन गया है और बाढ़ की घटनाओं को कम से कम करने और बाढ़ के असर को रोकने का प्रयास लगातार जारी है। इसके चलते शोधकर्ताओं ने एक वैकल्पिक नजरिया तैयार किया है, जिसे इको-डीआरआर कहा जा रहा है, जो आपदाओं और उसके असर पर अंकुश लगाने का काम करता है। इसके लिए वह मौजूदा पर्यावरणीय संसाधनों, विशेष रूप से कृषि भूमि का उपयोग करने का प्रयास करता है। नदियों के संगम के पास कृषि भूमि पानी को सोखने में मदद

कर सकती है और चरम मौसम की घटनाओं के दौरान बाढ़ की प्रगति को धीमा कर सकती है। नदियों के संगम के पास कृषि भूमि पानी को सोखने में मदद कर सकती है और चरम मौसम की घटनाओं के दौरान बाढ़ की प्रगति को धीमा कर सकती है। फोटो साभार- टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी

फसलों के उत्पादन के लिए कृषि लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़ी मात्रा में पानी को सोखकर और अस्थायी रूप से रोककर बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इसकी प्रभावकारिता व्यापक रूप से कृषि भूमि के स्थान और इसे कैसे बनाए रखा जाता है, इस पर निर्भर करती है।

शोधकर्ताओं ने कहा है कि जापान आपदा को कम करने के लिए इको-डीआरआर के प्रभाव का अध्ययन करने के प्रयासों में सबसे आगे हैं। जापान एक विशेष रूप से पहाड़ी देश है, जहां खेती की जमीन के बड़े हिस्से को बनाए रखना मुश्किल है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर लोगों के पलायन के कारण पूर्व में कृषि भूमि को छोड़ दिया गया या शहरीकरण किया गया। इस प्रकार बाढ़ के खतरों में कृषि उपयोग की विशिष्ट भूमिका को समझना तेजी से अहम होता जा रहा है।

एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील दिल्ली, गाजियाबाद में भी लगा सांसों पर आपातकाल



नई दिल्ली। दिल्ली में 54 अंकों के उछाल के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक 433 तक पहुंच गया है। इसी तरह गाजियाबाद में भी एक्वआई 400 के पार है साल खत्म होते-होते दिल्ली में एक बार फिर बढ़ता प्रदूषण आपात स्थिति में पहुंच गया। हालात यह हैं कि दिल्ली में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। कल से देखें तो 54 अंकों के उछाल के साथ दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 433 तक पहुंच गया है। मतलब की दिल्ली की हवा एक बार फिर पूरी तरह जहरीली हो चुकी है।

कुछ ऐसी ही स्थिति गाजियाबाद में भी है जहां सांसों पर आपातकाल लग चुका है। बता दें कि गाजियाबाद

में भी एक्वआई बढ़कर 400 के पार पहुंच गया है। गौरतलब है कि प्रदूषण के मामले में दिल्ली की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। इसी तरह अंगुल सहित देश के 15 शहरों में वायु गुणवत्ता %बेहद खराब% दर्ज की गई है। इन शहरों में बहादुरगढ़, भिवानी, बर्नीहाट, धौलपुर, दुर्गापुर, ग्रेटर एडा, गुरुग्राम, ग्वालियर, जींद, मेरठ, नारनौल, नोएडा, रोहतक, सोनीपत शामिल हैं, जहां एक्वआई 300 से 395 के बीच बना हुआ है। खास तौर पर बहादुरगढ़ और नोएडा में स्थिति कहीं ज्यादा खराब है, जहां सूचकांक 400 के करीब है। वहीं कल से तुलना करें तो बेहद खराब हवा वाले शहरों की संख्या में करीब 88 फीसदी का इजाफा हुआ है। प्रदूषण के मामले में दिल्ली का पड़ोसी शहर फरीदाबाद भी पीछे नहीं है, जहां 71 अंकों के उछाल के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक 265 तक पहुंच गया। फरीदाबाद की तरह ही देश के छोटे बड़े 50 अन्य शहरों में वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। इन शहरों में अगरतला, अहमदनगर, आसनसोल, बागपत, बल्लभगढ़, बैरकपुर, भागलपुर, भरतपुर, भिवाड़ी, भोपाल, भुवनेश्वर, बिहार शरीफ, बीकानेर, बुलन्दशहर, चंडीगढ़, चुरू, दमोह, देहरादून, धारूहेड़ा, फरीदाबाद, गुम्मिडिपूंडी, हाजीपुर, हल्दिया, हनुमानगढ़, हिसार, हावड़ा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, कैथल, करनाल, कटनी, खुर्जा, कोलकाता, कोटा, लखनऊ, मंडीदीप, मानेसर, पानीपत, परभनी, पटना, रानीपेट, राउरकेला, सहरसा, सासाराम, तालचर, तिरुपति, टोंक, वेल््लोर, वृंदावन शामिल हैं। हालांकि कल से देश में खराब हवा वाले शहरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है और स्थिति जस की तस बनी हुई है।

जलवायु

सदी के अंत तक विलुप्त हो जाएंगी एक तिहाई प्रजातियां, कौन है जिम्मेवार ?



शिमला(एजेंसी) वैज्ञानिक वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन पर लगाम न लगाई गई तो सदी के अंत तक मौजूदा एक तिहाई प्रजातियां धरती से विलुप्त हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से जुड़े जीवविज्ञानी मार्क सी अर्बन द्वारा किए इस अध्ययन के नतीजे अंतराष्ट्रीय जर्नल साइंस में प्रकाशित हुए हैं। अपने इस अध्ययन में उन्होंने पिछले तीन दशकों में प्रकाशित 485 अध्ययनों का विश्लेषण किया है। इसमें बताया गया है कि कैसे प्रजातियां जलवायु में आते बदलावों के प्रति अनुकूल होती हैं।

रिसर्च से पता चला है कि इन प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए हम ही जिम्मेवार हैं। इंसानों की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन हवा और

महासागरों को गर्म कर रहा है। इसकी वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव हो रहे हैं जो आगे भी जारी रहेंगे। इसकी वजह से जहां कुछ जगहों पर बेहद अधिक बारिश होगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्र जरूरत से ज्यादा गर्म और शुष्क हो जाएंगे। इस बात की भी आशंका है कि दुनिया को सूखा, आंधी, तूफान और लू जैसी कई और भी चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह घटनाएं पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी हो जाएंगी। वातावरण में आते ये बदलाव दूसरे जीवों और पौधों के लिए जीवन कठिन बना देंगे। यह जीव हम इंसानों की तरह अनुकूलन नहीं कर सकते, ऐसे में आने वाले समय में इनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अपने इस अध्ययन में जीवविज्ञानी मार्क सी अर्बन ने 485 अन्य शोधों की समीक्षा की है। इसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि यह प्रजातियां वातावरण और जलवायु में आते बदलावों का सामना कैसे कर सकती हैं। इसमें उनके जलवायु अनुकूलन की क्षमता का भी विश्लेषण किया गया है। इसकी वजह से जहां कुछ जगहों पर बेहद अधिक बारिश होगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्र जरूरत से ज्यादा गर्म और शुष्क हो जाएंगे। इस बात की भी आशंका है कि दुनिया को सूखा, आंधी, तूफान और लू जैसी कई और भी चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह घटनाएं पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी हो जाएंगी। वातावरण में आते ये बदलाव दूसरे जीवों और पौधों के लिए जीवन कठिन बना देंगे। यह जीव हम इंसानों की तरह अनुकूलन नहीं कर सकते, ऐसे में आने वाले समय में इनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने इन आंकड़ों की तुलना भविष्य में तापमान में होने वाली वृद्धि से की है ताकि यह देखा जा सके कि इसकी वजह से विभिन्न क्षेत्रों में क्या बदलाव आ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रजातियों के आवास, प्रवास और अनुकूलन क्षमता के आधार पर प्रजातियों के जीवित बचे रहने की संभावनाओं का भी अनुमान लगाया है। रिसर्च के जो नतीजे सामने आए हैं वो दर्शाते हैं कि यदि सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 5.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, जैसा कि सबसे खराब परिस्थितियों में होने का अंदेशा जताया गया है, तो इसके साथ ही दुनिया की एक तिहाई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं।

भारत में धोबी घाटों से बढ़ रहा नदियों और झीलों में माइक्रोफाइबर प्रदूषण- रिपोर्ट



नई दिल्ली। भारत के पारंपरिक खुले में कपड़े धोने की जगहें, जिन्हें धोबी घाट कहा जाता है, ये सांस्कृतिक महत्व रखते हैं और पीढ़ियों से हजारों धोबियों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन इन धुलाई वाली जगहों को अब माइक्रोफाइबर के रूप में एक आधुनिक पर्यावरणीय चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये पानी में रहने वाले जीवों और लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं।

शोध पत्र के अनुसार धुलाई के दौरान कपड़ों से निकलने वाले छोटे सिंथेटिक रेशे और कण भारत में नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों को प्रदूषित कर रहे हैं। माइक्रोफाइबर प्रदूषण एक खामोश लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ चिंताजनक मुद्दा है। कपड़ों की धुलाई के दौरान लाखों सिंथेटिक फाइबर बह जाते हैं, खास तौर पर धोबी घाटों और व्यावसायिक लॉन्ड्रियों में, जहां अक्सर छानने की प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये फाइबर या रेशे जल निकायों में मिल जाते हैं, समय के साथ जमा होते हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रुकावट पैदा करते हैं। श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में धोबी घाटों और इसी तरह के व्यावसायिक लॉन्ड्रियों से निकलने वाले पानी में माइक्रोफाइबर के स्तर को मापा गया है। एनवायर्नमेंटल साइंस एंड पोल्यूशन रिसर्च नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, धोबी घाट प्रति लीटर कचरे वाले पानी में 3,200 से अधिक माइक्रोफाइबर छोड़ते हैं, जबकि व्यावसायिक लॉन्ड्रियां प्रति लीटर लगभग 37,000 माइक्रोफाइबर छोड़ती हैं। इनमें से अधिकांश कण पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे सिंथेटिक कपड़ों से आते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। पानी में जाने के बाद ये माइक्रोफाइबर पानी में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं और आखिर में लोगों के खाद्य श्रृंखला में अपना रास्ता बना लेते हैं। कश्मीर में झेलम नदी और डल झील क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और मछुआरों सहित हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। हालांकि माइक्रोफाइबर प्रदूषण भयंकर खतरा पैदा करता है, जो वन्यजीवों और लोगों दोनों को प्रभावित करता

है। श्रीनगर में कई धोबी घाट झेलम नदी के किनारे चलते हैं, इन घाटों से निकलने वाला गंदा पानी बिना उपचार किए नदी में बह जाता है। डल झील और झेलम नदी श्रीनगर के हजारों परिवारों के लिए जीवनरेखा हैं। बढ़ता माइक्रोफाइबर प्रदूषण एक खामोश आपदा है जिसका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। शोध के मुताबिक, कई धोबी यहां कई पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, नदी उनके काम और जीवन का अहम हिस्सा है। यह उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। एक स्थानीय धोबी ने शोधकर्ताओं को बताया कि यदि काम करने के तरीके को रोकने या बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमारे परिवारों का क्या होगा? धोबी और अन्य लोग असहाय महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास संसाधनों और विकल्पों के बारे में जानकारी की कमी है। धोबी ने शोधकर्ताओं को बताया कि किसी ने हमारा मार्गदर्शन नहीं किया है या हमें किराया समायोजन नहीं दिया है। हमें सरकार

और विशेषज्ञों से मदद की जरूरत है। घाट धोबियों की विरासत का हिस्सा है। यह काम उन्हें अपने पिता और दादाओं से विरासत में मिला है। यह मात्र एक काम नहीं है, यह उनकी पहचान है। शोध के दौरान धोबी घाट समुदाय के एक बुजुर्ग ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा यह काम हमें सदियों से विरासत में मिला है। नदी में कपड़े धोना सिर्फ आजीविका नहीं है, यह एक कला और जिम्मेदारी है जिसे हमने गर्व के साथ निभाया है। उन्होंने कहा कि समय बदल रहा है और हमें अपनी विरासत और हमें पोषण देने वाले पानी दोनों की रक्षा के लिए मार्गदर्शन की जरूरत है। माइक्रोफाइबर के साथ-साथ केमिकल डिटर्जेंट जलीय जीवन और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं, जबकि अनुपचारित सीवेज कई नदियों में समा जाता है। शोधकर्ता धोबी घाटों पर किरायाती माइक्रोफाइबर फिल्टर लगाने का सुझाव देते हैं। ये फिल्टर अपशिष्ट जल के जल निकायों में जाने से पहले सिंथेटिक फाइबर को रोक सकते हैं। उचित अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों वाली कपड़े धोने की सुविधाएं भी मदद कर सकती हैं। इससे प्रदूषण कम होगा और धोबियों के लिए काम करने की स्थिति में सुधार होगा। अन्य समाधानों में बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का उपयोग करना और धोबियों के बीच पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी शामिल है। शोध के मुताबिक स्थानीय निवासी और संगठन भी सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। श्रीनगर निवासी धोबियों के लिए वित्तीय सहायता और शिक्षा कार्यक्रमों की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, वे अनुकूलन के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें संसाधनों और समर्थन की जरूरत है। यह एक साझी जिम्मेदारी है। पर्यावरण समूह भी माइक्रोफाइबर प्रदूषण को कम करने में घरों की भूमिका पर जोर दे रहे हैं। शोधकर्ताओं ने शोध के हवाले से कहा कि उन्हें, श्रीनगर स्थित एनजीओ के सदस्य ने कहा कि यह समस्या घर से शुरू होती है क्योंकि हम सभी सिंथेटिक कपड़ों इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आगे कहा, लोगों को इस बात के बारे में जागरूक होने की जरूरत है कि उनके कपड़े धोने के विकल्प पर्यावरण पर किस तरह से बुरा प्रभाव डाल रहे हैं।

इंदौर मॉडल को पूरे प्रदेश में पहुंचाने का प्रयास-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग क्षेत्र के साथ ही अन्य क्षेत्रों में इंदौर की महत्वपूर्ण भूमिका है। सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर निवेश के विभिन्न क्षेत्रों में इंदौर में आने वाले कल की आहट सुनकर विकास पथ पर कदम बढ़ाए हैं। इसलिए इंदौर मध्यप्रदेश का सिरमौर है।

इंदौर एक ग्लोबल सिटी है। चाहे यहां खान-पान की बात हो, कला जगत की बात हो, परम्पराओं को सहेजने की बात हो या फिर स्वच्छता में सबसे आगे रहने की। इंदौर एक मॉडल है। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और समिट के इंदौर मॉडल को पूरे प्रदेश में पहुंचाया गया है। प्रदेश के विभिन्न संभागों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर मध्यप्रदेश के तीव्र विकास को गति देने की पहल हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से वर्चुअली जुड़कर इंदौर में एनआरआई फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस समिट में 29 देशों के 128 प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नदी जोड़ो परियोजनाओं का पहला प्रयोग कर एक रिकार्ड बनाया है। मध्यप्रदेश दोनों परियोजनाओं में शामिल है। केन-बेतवा परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना से मध्यप्रदेश के बड़े इलाके में पेयजल और सिंचाई के लिए बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। समृद्धि के नए मार्ग खुलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज जयपुर में पार्वती-काली सिंध-चंबल परियोजना संबंधित त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ है।

पृथ्वी एवं मानव जाति की उत्पत्ति और विकास की अनूठी जानकारियां उपलब्ध हैं म्यूजियम में

डायनासोर का अण्डा भी देखा जा सकता है म्यूजियम में

इंदौर (नगर प्रतिनिधि) उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम (भू-विज्ञान संग्रहालय) का रविवार को उद्घाटन किया। ग्वालियर के ऐतिहासिक महाराज बाड़ा पर हैरीटेज बिल्डिंग विक्टोरिया मार्केट में स्थापित अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय संचार व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे, विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट एवं सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह भी मौजूद थे। इस अवसर पर उप राष्ट्रपति की धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ विशेष रूप से उपस्थित रही।

उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने पट्टिका का अनावरण कर एवं म्यूजियम के प्रवेश द्वार पर फीता काटकर देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया। साथ ही

ग्वालियरवासियों को इस अनूठी सौगात की बधाई एवं शुभकामनायें दीं। उन्होंने सभी अतिथियों के साथ म्यूजियम की विभिन्न गैलरियों में दर्शाए गए भू-विज्ञान से संबंधित चित्रों, कलाकृतियों एवं जानकारियों को देखा एवं म्यूजियम की सराहना की। म्यूजियम के उद्घाटन के बाद उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने महाराज बाड़ा पर स्थित वास्तु शिल्प के उत्कृष्ट नमूनों के रूप में खड़ी ऐतिहासिक इमारतों को भी देखा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया एवं विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने उप राष्ट्रपति को महाराज बाड़े की इमारतों के शिल्प एवं शैलियों से अवगत कराया। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा ग्वालियर नगर निगम के सहयोग से तैयार किए गए देश के इस पहले अत्याधुनिक एवं अद्भुत जियो साइंस म्यूजियम में पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव जाति एवं मानव सभ्यता का विकास और ब्रह्माण्ड से जुड़ी अनूठी जानकारियाँ समाहित हैं। म्यूजियम में डायनासोर का अण्डा सहित कीमती वस्तुएँ

पर्यटकों को देखने के लिये उपलब्ध हैं। यह म्यूजियम भू-विज्ञान से संबंधित बच्चों से लेकर बड़ों तक की जिज्ञासाओं का समाधान उपलब्ध है। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह संग्रहालय ज्ञानवर्धक है। पृथ्वी विज्ञान से संबंधित दुर्लभ भू-वैज्ञानिक नमूनों को मल्टीमीडिया डिस्प्ले के जरिए म्यूजियम में दिखाया गया है। जियो साइंस म्यूजियम में दो गैलरियों के माध्यम से भू-विज्ञान के बारे में लाइट इफेक्ट के साथ आकर्षक ढंग से जानकारी संचोई गई है। एक गैलरी में पृथ्वी के विकास को दर्शाया गया है, जिसमें उल्लेख है कि पृथ्वी अपने मूल स्वरूप में किस प्रकार आई और कौन-कौन सी चीजों से मिलकर पृथ्वी बनी है। वर्तमान में जो पृथ्वी है, असल में वह कैसी दिखती है। पृथ्वी के भीतर लावा किस तरह से तैयार होता है और ज्वालामुखी फूटने से किस तरह पर्वतों का निर्माण होता है। यह सब जानकारियां बखूबी ढंग से संग्रहालय में दर्शायी गई हैं। यहाँ

आने वाले पर्यटन भूकम्प का अनुभव भी कर सकेंगे। इसके अलावा वायु मण्डल और महासागर के बारे में भी वर्णन है। लाइट इफेक्ट और अत्याधुनिक मशीनी तकनीक से बड़े बखूबी ढंग से यह सब प्रदर्शित किया गया है। जियो साइंस म्यूजियम की दूसरी गैलरी में मानव जाति और मानव सभ्यता के विकास को बड़े बखूबी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि धरती पर डायनासोर की उत्पत्ति और विलुप्ति हुई। साथ ही मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे उसका जीवनक्रम आगे बढ़ा। मानव सभ्यता की जीवन शैली में आए बदलाव का यह वर्णन भी दर्शनीय है। जियो साइंस म्यूजियम के उद्घाटन कार्यक्रम में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक श्री असित साहा, संभाग आयुक्त श्री मनोज खत्री, पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविंद सक्सेना, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक श्री

धर्मवीर सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री अमन वैष्णव एवं जियो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी भी मौजूद थे। उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का रविवार को ग्वालियर एयरबेस पर आगमन हुआ। विमानतल पर उप राष्ट्रपति का राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। उप राष्ट्रपति के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ और केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए। इस अवसर पर ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह, पूर्व मंत्री श्रीमती माया सिंह, श्रीमती इमरती देवी, विधायक श्री मोहन सिंह राठौर, पूर्व विधायक श्री मुन्नालाल गोयल, श्री रमेश अग्रवाल एवं श्री रामबरन सिंह गुर्जर सहित जन-प्रतिनिधियों ने उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ का स्वागत किया।

रातापानी टाइगर रिजर्व पार्क में बढ़ेगा पर्यटन, 17 साल बाद 90 बाघों को मिला अपना घर



नेपाल। मग्न में बाघों के संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। यह राज्य का आठवां टाइगर रिजर्व है, जहां लगभग 90 बाघ रहते हैं। यह फैसला काफी समय से लंबित था। 2008 में एनटीसीए से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाने में देरी की थी।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से राज्य सरकार को अधिसूचना प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। उन्होंने इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष और बाघों की आबादी की रक्षा की जरूरत का हवाला दिया था। अब रातापानी टाइगर रिजर्व पार्क बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित है। यह बाघों के एक महत्वपूर्ण आवास का हिस्सा है। हाल के वर्षों में, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से बाघ इस अभयारण्य और आसपास के वन क्षेत्रों में आने लगे हैं। बाघों के इन इलाकों में आने के बाद, 2007 में राज्य सरकार ने रातापानी और सिंघोरी अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। एनटीसीए ने 2008 में रिजर्व के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। राज्य वन विभाग को रिजर्व की सीमाओं और कोर क्षेत्रों के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।